

इस्लामी वित्तीय संस्थाएं

31 दिसम्बर 1993 ई0 - 3 जनवरी 1994 ई0 उमराबाद में आयोजित छठे फ़िक्रही सेमिनार में
इस्लामी वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित एक अहम फैसला यह किया गया कि:

“वित्तीय संस्थाओं को अपनी पूँजी का पांच फ़ीसदी हिस्सा रिझर्व बैंक के नियम की वजह से सरकारी संरक्षण में जमा रखना पड़ता है, जिस पर सरकार ब्याज भी देती है। इस स्थिति में जमा पूँजी पर मिलने वाले ब्याज को धीरे-धीरे सुरक्षित पूँजी बना दिया जाए और मूल पूँजी धीरे धीरे उसमें से निकाल ली जाए।

☆☆☆